PRESS NOTE

24-08-2022

महामारी के बाद के गवाहों में स्टार्ट-अप का भारी उछाल

कृषि-ग्रामीण क्षेत्र, एमएसएमई ईपीसी सर्वेक्षण

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक-जिला-एक-उत्पाद (ओडीओपी) के माध्यम से की गई कई नीतिगत पहलों ने कृषि-ग्रामीण आधारित उद्योगों और युवाओं को नौकरी चाहने वालों से नौकरी प्रदाता बनने के लिए जबरदस्त बढ़ावा दिया है।

COVID-19 के कारण बड़ी संख्या में सूक्ष्म, लघु और मध्यम इकाइयों के बंद होने / बड़ी संख्या में नौकरी के नुकसान ने अब राज्य के युवाओं, शिल्पकारों और उद्यमी किसानों को ODOP की विभिन्न योजनाओं के तहत अपने स्वयं के सूक्ष्म उद्यम शुरू करने के लिए प्रेरित किया है।

नॉलेज फर्म बिलमार्ट फिनटेक के साथ एमएसएमई एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल द्वारा किए गए त्वरित सर्वेक्षण से पता चला है कि ये उद्यम न केवल कम पूंजी लागत पर बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, बल्कि ग्रामीण और औद्योगिकीकरण के लिए प्रभावी हो रहे हैं। जिससे राष्ट्रीय आय और धन के अधिक समान वितरण को सुनिश्चित करते हुए, क्षेत्रीय असंतुलन को कम किया जा सके।

एमएसएमई ईपीसी के अध्यक्ष डी एस रावत द्वारा मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ को प्रस्तुत किए गए सर्वेक्षण में कहा गया है कि ये उद्यम सहायक के रूप में बड़े और मध्यम स्तर की इकाइयों के पूरक और पूरक साबित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने एमएसएमई ईपीसी को वैश्विक स्तर पर एमएसएमई की सहायता करने के लिए कहा ताकि वे निर्यात बाजार में अपनी हिस्सेदारी बढ़ा सकें। पहले से ही, एमएसएमई उद्योग रोजगार सृजन और विदेशी मुद्रा आय के स्रोत के रूप में और कुल औद्योगिक उत्पादन का लगभग 65 प्रतिशत के रूप में राज्य की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण खंड है।

आज यहां जारी एक बयान में, रावत ने कहा, एमएसएमई ईपीसी और बिलमार्ट ने एमएसएमई और स्टार्ट-अप्स के लिए काम करने के लिए एक जिले को "पायलट प्रोजेक्ट" के रूप में अपनाने का फैसला किया है, ताकि वे अपने व्यवसायों के विकास के लिए प्रतिस्पर्धी और समय पर क्रेडिट लेने के लिए तैयार हो सकें। उन्हें खरीदार/विक्रेता, प्रौद्योगिकी और क्रेडिट प्रदाताओं से जुड़ने के लिए तकनीकी कौशल भी प्रदान किया जाएगा।

ये दोनों संगठन भुगतान जोखिम और आपूर्ति जोखिम को दूर करने के लिए लेनदेन के लिए तीसरे पक्ष को पेश करने की दृष्टि से व्यापार वित्त को बढ़ावा देंगे। व्यापार वित्त की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए, रावत ने कहा कि व्यापार वित्त निर्यातक को समझौते के अनुसार प्राप्य या भुगतान प्रदान करता है जबकि आयातक को व्यापार आदेश को पूरा करने के लिए क्रेडिट बढ़ाया जा सकता है।

2022 में भारत का व्यापार वित्त 2.75 बिलियन अमरीकी डालर होने का अनुमान है और 2027 तक 3.90 बिलियन अमरीकी डालर को पार करने की उम्मीद है जो 7 प्रतिशत से अधिक की सीएजीआर से बढ़ रहा है।

एलाइड मार्केट रिसर्च के अनुसार, वैश्विक व्यापार वित्त बाजार का आकार 2020 में 44,098 मिलियन डॉलर था और 2030 तक 90,212 मिलियन डॉलर तक पहुंचने का अनुमान है। 2021-2030 तक 7.4 प्रतिशत की सीएजीआर दर्ज करना।

यह उल्लेख किया जा सकता है कि व्यापार वित्त में ऋण पत्र (एलसी), प्राप्य और चालान वित्त, क्रेडिट एजेंसी, निर्यात वित्त, बैंक गारंटी और बीमा जारी करना शामिल है। इसका उपयोग व्यापारियों, खरीदारों, विक्रेताओं, निर्माताओं, आयातकों और निर्यातकों द्वारा वित्तीय गतिविधियों को आसान बनाने और व्यापार उद्देश्यों के लिए नकद, क्रेडिट, निवेश और अन्य संपत्तियों से निपटने के लिए किया जाता है।

रावत ने कहा, व्यापार वित्त का प्रमुख लाभ यह है कि यह अल्पकालिक वित्त की व्यवस्था करने का आसान तरीका है और व्यापार वित्त में ब्लॉक श्रृंखला प्रौद्योगिकी के एकीकरण से पूर्वानुमान अवधि के दौरान आकर्षक व्यापार वित्त बाजार अवसर प्रदान करने की उम्मीद है।

****